



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052024-254018  
CG-DL-E-03052024-254018

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1789]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 2, 2024/वैशाख 12, 1946

No. 1789]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 2024/VAISAKHA 12, 1946

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2024

का.आ. 1881(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार, किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, “पीएम केयर्स बालकों के लिए छात्रवृत्ति”(2022-2023 से 2025-26)के लिए केंद्रीय सेक्टर स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का ऐसे बालकों को जिन्होंने अपने दोनों माता-पिता या विधिक संरक्षक या दत्तक माता-पिता या उतरजीवी माता-पिता को कोविड 19 महामारी में खो दिया है, कक्षा 1 से आगे कक्षा 12 तक अध्ययन पूरा करने के लिए, संचालन कर रहा है, जिसका सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है;

और, स्कीम के अधीन, स्कीम और उसके अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के विस्तार तक, कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा ऐसे बालकों जिन्होंने अपने दोनों माता-पिता या विधिक संरक्षक या दत्तक माता-पिता या उतरजीवी माता-पिता को कोविड 19 महामारी में खो दिया है, (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को ऐसे बालकों जिन्होंने अपने

दोनों माता-पिता या विधिक संरक्षक या दत्तक माता-पिता या उतरजीवी माता-पिता को कोविड 19 महामारी में खो दिया है, के सहयोग के लिए छात्रवृत्ति सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) दी जाती है;

और, स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से उपगत किया गया आवर्ती व्यय सम्मिलित है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन से गुजरने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति से, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, माता-पिता या अभिभावकों (बालक फायदाग्राही की दशा में) की सहमति के अधीन रहते हुए आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जाएगी, परंतु वह स्कीम के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे बालक, आधार के लिए नामांकित कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध सूची) पर जाएं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परंतु कि जब तक व्यक्ति को आधार नहीं दिया जाता है, तब तक स्कीम के अधीन फायदा ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा, जो निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के अधीन हैं, अर्थात्:-

I. अठारह वर्ष से छोटे बालकों के लिए-

- (क) (i) यदि फायदाग्राही को पांच वर्ष की आयु के पश्चात् (बायोमेट्रिक संग्रह के साथ) नामांकित किया गया था, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मैट्रिक अपडेट पहचान पर्ची, या;
- (ii) फायदाग्राही द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति; और
- (ख) फायदाग्राही के निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:
  - (i) समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण -पत्र या जन्म का अभिलेख; या
  - (ii) माता-पिता के नाम वाले स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित स्कूल पहचान पत्र; और
- (ग) स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विस्तार के अनुसार माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ फायदाग्राही के संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक:
  - (i) समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण -पत्र या जन्म का अभिलेख; या
  - (ii) राशन कार्ड, या
  - (iii) भूतपूर्व सैनिक अभिदाय स्वास्थ्य स्कीम कार्ड ; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्ड ; या केन्द्रीय कार्ड स्वास्थ्य स्कीम कार्ड ; या
  - (iv) पेंशन कार्ड ; या
  - (v) सेना कैप्टीन कार्ड ; या
  - (vi) कोई भी सरकारी कुटुंब हकदारी कार्ड ; या
  - (vii) कोई अन्य दस्तावेज जो मंत्रालय या विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है ;

## II. 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के फायदाग्राहियों के लिए :

(क) यदि उसने नामांकन किया है तो, आधार नामांकन पहचान पर्ची ; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात् :-

- (i) फोटो सहित बैंक या डाकघर पासबुक ; या
- (ii) स्थायी लेखा संख्याक कार्ड ; या
- (iii) पासपोर्ट ; या
- (iv) राशनकार्ड ; या
- (v) मतदाता पहचान कार्ड ; या
- (vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड ; या
- (vii) किसान फोटो पासबुक ; या
- (viii) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति ; या
- (ix) शासकीय लेटर हैड पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी ऐसे व्यक्ति का फोटो सहित पहचान प्रमाणपत्र ; या
- (x) कोई अन्य दस्तावेज, जो मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु यह और कि पूर्वोक्त दस्तावेजों की इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय या विभाग द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी ।

2. मंत्रालय या विभाग स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक रूप से फायदे प्रदान करने के लिए अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा कि स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा से उन्हें जागरूक करने के लिए फायदाग्राहियों को मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए ।

3. जहां आधार अधिप्रमाणन फायदाग्राहियों के खराब बायोमैट्रिक्स या किसी अन्य कारण से असफल हो जाता है तो निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्रों को अंगीकृत किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) खराब अंगुलछाप क्वालिटी की दशा में अधिप्रमाणन के लिए पुतली स्कैन या चेहरे की अधिप्रमाणन सुविधा को अंगीकृत किया जाएगा और मंत्रालय या विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से स्कैनरों या चेहरे के अधिप्रमाणन के साथ अंगुलछाप अधिप्रमाणन का निर्बाध रीति में फायदों के परिदान के लिए उपबंध करेंगे ;

(ख) अंगुलछाप या पुतली स्कैन या चेहरे के अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन के असफल होने की दशा में जहां कहीं साध्य हो और अनुज्ञेय हो, यथास्थिति, आधार एक बार पासवर्ड या समय आधारित एक बार पासवर्ड जिसकी सीमित विधिमान्यता हो, का प्रस्ताव किया जाएगा ;

(ग) सभी अन्य मामलों में जब बायोमैट्रिक या आधार एक बार पासवर्ड या समय आधारित एक बार पासवर्ड के माध्यम से अधिप्रमाणन संभव नहीं होता है तो स्कीम के अधीन फायदों को भौतिक आधार पत्र के आधार पर जिसकी अधिप्रमाणता का आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रेसपोंस कोड के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है, दिया जा सकता है और क्विक रेसपोंस कोड रीडर के लिए आवश्यक इंजाम मंत्रालय या विभाग द्वारा उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर किए जाएंगे ।

4. यहां उपरोक्त अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी बालक को स्कीम के अधीन फायदों का उसकी अधिप्रमाणन के माध्यम से या आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करने में असफलता या ऐसे बालक की दशा में, जिसे कोई आधार संख्या नहीं दी गई है, द्वारा नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में असफलता की दशा में उसे अन्य दस्तावेजों, जो पैरा 1 के उपपैरा (3) के परंतुक के खंड (1) के उपखंड (ख) और उपखंड (ग) में वर्णित किए गए हैं, के आधार पर पहचान का सत्यापन करने पर फायदे प्रदान किए जा सकेंगे, इसे अभिलिखित करने के लिए एक पृथक रजिस्टर रखा जाएगा जिसका मंत्रालय या विभाग द्वारा कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से पुनर्विलोकन और संपरीक्षा की जाएगी ।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम के अधीन किसी सदभावी फायदाग्राही (बालकों से भिन्न) को उसके सम्यक् फायदों से वंचित नहीं किया जाता है, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रत्यक्ष फायदा अंतरण मिशन कार्यालय ज्ञापन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार सं. डी -26011/04/2-17-डीजीटी, तारीख 19 दिसंबर, 2017 (<https://bbpbharat.gov.in/>) में यथाविनिर्दिष्ट के माध्यम से अपवाद हैंडिंग तंत्र का अंतरण करेगा।

6. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.14017/4/2023-डीबीटी]

बिस्वारंजन सासमल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2024

**S.O.1881(E).**— Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as the Department) in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, is administering the Central Sector Scheme of “Scholarship for PM CARES Children” (2022-23 to 2025-26) (*hereinafter referred to as the Scheme*) with an objective to provide Scholarship assistance to support Children who have lost both the Parents or legal Guardian or Adoptive Parents or surviving Parent to Covid 19 pandemic to complete their education from Class I onwards till they complete education till Class 12, which is being implemented through the Department of Social Justice & Empowerment (*hereinafter referred to as the Implementing Agency*);

And whereas, under the Scheme, Scholarship assistance to support Children who have lost both the Parents or legal Guardian or Adoptive Parents or surviving Parent to Covid 19 pandemic (*hereinafter referred to as the benefit*) is given to the Children who have lost both the Parents or legal Guardian or Adoptive Parents or surviving Parent to Covid 19 pandemic (*hereinafter referred to as the beneficiaries*), by the Implementing Agency as per the Scheme and extant guidelines issued thereunder;

And whereas, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India.

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) an individual desirous of availing the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;
- (2) any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians (in case of child beneficiaries), provided he is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act, and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;
- (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry or Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry or Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves;

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely :-

#### I. For children below 18 years old:

- (a) (i) if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip, or;

- (ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary; and
- (b) any one of the following identity documents of the beneficiary, namely:-
  - (i) Birth Certificate or record of birth, issued by the appropriate authority; or
  - (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents name; and
- (c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:-
  - (i) Birth Certificate; or record of birth, issued by the appropriate authority or
  - (ii) Ration Card; or
  - (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme Card; or Employees' State Insurance Corporation Card; or Central Government Health Scheme Card; or
  - (iv) Pension Card; or
  - (v) Army Canteen Card; or
  - (vi) any Government Family Entitlement Card; or
  - (vii) any other document as specified by the Ministry or Department;

II. For beneficiaries of 18 years old and above:

- (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
- (b) any one of the following documents, namely :-
  - (i) Bank or Post office Passbook with Photo; or
  - (ii) Permanent Account Number Card; or
  - (iii) Passport; or
  - (iv) Ration Card; or
  - (v) Voter Identity Card; or
  - (vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act card; or
  - (vii) Kisan Photo passbook; or
  - (viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
  - (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
  - (x) any other document as specified by the Ministry

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry or Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry or Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. Where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

- (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Ministry or Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
- (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One-Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
- (c) in all other cases where biometric or Aadhaar One-Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the

Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry or Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in sub clauses (b) and (c) of Clause (I) of the proviso to sub paragraph (3) of paragraph 1 and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry or Department through the implementing Agency.

5. In order to ensure that no bona fide beneficiary (other than children) under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19<sup>th</sup> December 2017 (available on <https://dbtbharat.gov.in/>).

6. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[F. No. 14017 /4/ 2023-DBT]

BISWARANJAN SASMAL, Jt. Secy.